श्री विष्णु कान्त शास्त्री: जैसा आप कहें।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): नहीं, वह तो आपके उसके पर है.....**(व्यवधान)**

श्री मूल चन्द मीणा। आपको तो अभी बहुत लोगों को सुनना है, तो मेहरबानी करके संक्षेप में बता दीजिए, क्योंकि दृष्टिकोण में ज्यादा विभिन्नता नहीं होगी।

Re: Discontinuation of Rebate of Khadi

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): उपसभाअध्यक्ष महोदय, मैं जिस विषय को इस सदन में उठाना चाहता हूं वह एक बहुत ही गंभीर विषय है। इस सरकार ने, खादी का जो भविष्य है उसको अंधकारमय बना दिया है। इस देश की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने चरखा संघ का 1923 के अंदर...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप वह विवरण छोड़ दीजिए।...**(व्यवधान)** आप पुराना विवरण छोड़ दीजिए, आज का बता दीजिए।

श्री मूलचन्द मीणा: सर, खादी पर जो रिबेट सरकार ने बंद की है इससे 15 लाख कारीगर, 50 लाख के करीब मजदूर, उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। खादी का उद्देश्य था। आजादी की लड़ाई लड़ने वालों की खादी एक पोशाक थी और हम 50वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। लेकिन समझ नहीं आता कि यह कैसी स्वतंत्रता की वर्षगांठ यह सरकार मनाना चाहती है? आजादी के दीवानों की पोशाक पर दी जाने वाली छूट, रिबेट, उसको सरकार ने बंद कर दिया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, खादी कमीशन के माध्यम से जो ग्रामोद्योग चल रहे हैं, उन पर 4 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता था, आज उस ब्याज की दर को 17 प्रतिशत कर दिया गया है। फिर यह कैसे संभव हो पाएगा? महोदय, इस देश में स्वदेशीकरण के लिए खादी उद्योग की स्थापना की गयी थी और खादी का उपयोग प्रारंभ किया गया था। उस खादी का इतनी प्रचुर मात्रा में प्रचार-प्रसार हुआ कि न केवल देश में लोग खादी के प्रति लालायित हुए बल्कि आज दूसरे देशों के लोगो में भी खादी के प्रति एट्रेक्शन बढ़ा है, लेकिन यह सरकार की समझ में नहीं आता है और उस ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाने वाले दीवानों की पोशाक पर जो रिबेट थी उस को। अप्रैल से बंद कर दिया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): उसे रिस्टोर कर दिया जाए, यही आप की मांग है।

श्री मूलचन्द मीणा: यह तो मांग है ही। रिबेट को चालू कीजिए। आजादी की पचासवीं वर्षगांठ पर गांधी जी की भावनाओं और देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की भावना का आदर करते हुए इस रिबेट को वापिस किया जाए। महोदय, इस देश के गांवों का विकास ही हिंदुस्तान का विकास है। जब तक गांवों का विकास नहीं होगा। तब तक हिंदुस्तान का विकास नहीं होगा। इसलिए खादी कमीशन के माध्यम से गांवों के अंदर जो ग्रामोद्योग लगे हैं, उन के लिए ब्याज की दर वही 4 प्रतिशत रखी जाए क्योंकि यह खादी का कार्य बहुत ही गरीब तबके के लोगों और बुनकरों द्वारा किया जाता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप ने काफी प्रभावी ढंग से अपनी बात कह दी। पंडित नेहरु जी ने कहा था कि

"Khadi is a livery of freedom".

आपने बड़े स्वाभाविक ढंग से अपनी बात कह दी।

श्री मूलचन्द मीणा: उपसभाअध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह 50 लाख मजदूरों, 15 लाख कारीगरों को निराश न करे और खादी पर अभी जो सुविधा दी जा रही है, वह बरकरार रखी जाय, इतना ही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): नायडू साहब, आप इस को ध्यान में रखें।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश): उपसभाअध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। मैं स्वयं को इस से सम्बद्ध करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): श्री अनन्तराय देवशंकर दवे। आप बहुत संक्षेप में अपनी बात कह दीजिए। आप तो संक्षेप में कहने के आदी हैं।

SPECIAL MENTIONS

Heavy Drought Prevailing in Kutch District of Gujarat

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात): उपसभाध्यक्ष मुझे इस हाउस में आए 6-7 साल हो गए हैं यह मेरा यहां दूसरा टर्म है। मैंने इस सदन में 5-6 बार यह बात उठायी है।

महोदय, हमारे यहां हर 10 साल में 4 स्केअरसिटी

वर्ष आते हैं और इस वर्ष भी स्केअरसिटी चल रही है, लेकिन पीने के पानी की कोई व्यवस्था आज दिन तक वहां नहीं की गयी है। महोदय, हमारे यहां करीब एक हजार गांव हैं जिन में से साढ़े चार सौ गांवों में टैंकर से पानी दिया जाता है। आज जो पानी हम पीते हैं वह करीब 1800 टी०डी०एस० से ज्यादा है और ह्यूमन हैल्थ के लिए प्रॉपर नहीं है। वह पानी लोग आज पीते हैं। महोदय, कच्छ के इलाके का जो वेस्टर्न पार्ट है, वह बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, आज वहां से लोग खिसकते-खिसकते दूसरी जगह जा रहे हैं। पीछे पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां से लोग जा रहे हैं।

महोदय, आज दिल्ली से करीब 18 करोड़ रुपया गुजरात गवर्नमेंट को दिया गया है, वहां विशेष तौर पर कच्छ के बनासकांठा और बनासकांठा में राजनपुर, जहां से कि गुजरात के मुख्य मंत्री ने चुनाव लड़ा, मैं उस जगह की बात कर रहा हूं, वहां रोड-साइड इकॉनोमी डवलप हुई है। नीदरलैंड सरकार की ओर से बनासकांठा जिले में करीब-करीब 70 गांवों के लिए पीने के पानी की सुविधा की गयी है। वहां रोड-साइड पर जितने पेट्रोल पंप हैं, हाइवे होटल्स हैं, उस जगह पूरी ग्रीनरी है, लेकिन जब हम गांवों में जाते हैं तो तीन-तीन दिन तक लोगों को पानी नहीं मिलता है।

महोदय, आप देखिए और जांच करवाइए कि आप का पैसा जो वहां गया है, उस का कैसा दुरुपयोग हो रहा है, विशेष तौर पर राजनपुर में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, कच्छ में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। इसी कारण वहां ड्राउट जैसे सिचुएशन है। हजारों कैटल तो मर चुके, कई बाहर चले गए। गवर्नमेंट को जो सबसिडी देनी चाहिए, ग्रास सबसिडी, ट्रांसपोर्ट सबसिडी, वह भी वहां नहीं मिलती है। आज वहां 50,000 लोग मजदूर के रूप में रोड का काम कर रहे हैं।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि वहां आप कोई ऐसा काम करवाएं क्योंकि अभी हजारों, करोड़ों रुपया कई सालों से इस डिस्ट्रिक्ट पर सरकार खर्च कर रही है, लेकिन दूसरे साल अगर पानी गिरेगा तो तीन साल फिर नहीं गिरेगा अर्थात् स्केयरसिटी की बात चलेगी। लोग जाएंगे, काम करेंगे, लेकिन कुछ उपयोग में आता नहीं है। मेरा सुझाव है कि कोई कन्क्रीट प्लान बनाकर वहां आप पैसा खर्च करें। इसका एक ही इलाज है और वह है सरदार सरोवर परियोजना। आप सरदार सरोवर के लिए सोचें। जितनी जल्दी से जल्दी यह कार्यक्रम हो जाएगा, उतनी ही जल्दी सौराष्ट्र, मेहसाना, कच्छ, बनासकत्कांठा आदि यह जो 7-8-9 डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां पानी की बड़ी असुविधा है, सुविधा होगी। आज जो 500, 700 फीट पर हमें पानी मिलता है, वह पानी भी पाटेबल वाटर नहीं है। मैं सरकार से विनम्र विनती करता हूं कि इस बारे में आप जरूर सोचें। आप रूरल डवलपमेंट मिनिस्टर यहां बैठे हैं, वहां लोगों को बड़ी तकलीफ है। आप देखें कि वहां लोगों को जल्दी से जल्दी कुछ पीने का पानी मिले और ड्राट जैसी स्थिति वहां की दूर हो। इसके लिए आप जरूर कुछ करें। मैं पहले भी तीन, चार, पांच बार इस बात को इस हाऊस में उठा चुका हूं, लेकिन आज तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। आप जरूर आज इस ओर कदम उठाइए। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Mr. Yerran Naidu will look into it.

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI YERRAN NAIDU K.): Sir, I will look into it.

Danger to Zuvari Bridge on National Highway No. 17 in Goa

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Sir, I would like to raise a problem about the Zuari bridge in Goa. Sir, in mid-eighties, there was a national tragedy and the Mandovi bridge in Panaji Goa had collapsed. The Zuari bridge too is of the same design. These are Russian designs which are not meant for saline rivers. These are bridges to be built in mountain cliffs. A wrong technology has been sent by the Central Government to the State of Goa. It was a newly liberated area from the Portuguese and this wrong technology has created an immense problem for the people of Goa. In 1987 when I was elected to this House, I had raised this problem. Again in 1992, when we are discussing the Konkan Railways, this issue was raised. There is already a parallel bridge to this bridge built by the Konkan Railway Corporation and I had suggested that this bridge be utilised for the road traffic. For the Railways, the cost would have been escalated by 40 per cent. Sir, I have been raising this issue repeatedly in this House and have been saying that the link on the National